आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 05.05.2023 से 11.06.2023)

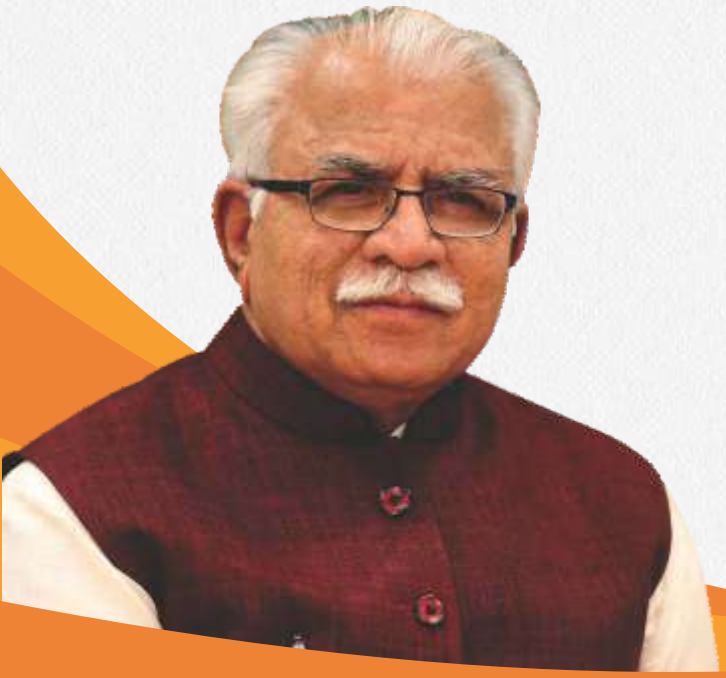

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

पंजाब विश्वविद्यालय से हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता पर अहम बैठक

(दिनांक 05.06.2023)

प्रभाव : पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारीलाल पुरोहित जी की अध्यक्षता में आज पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के विभिन्न विषयों को लेकर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के साथ बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के कॉलेजों की पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से संबद्धता के विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे संबंधित अगले दौर की बैठक 3 जुलाई सुबह 11 बजे होगी। श्री बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि भारत की संस्कृति शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की रही है। इसलिए पंजाब विश्वविद्यालय से हरियाणा के कॉलेजों को संबद्धता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 3 जिलों पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता के विकल्प देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्रों के हितों के लिए राज्य के कॉलेजों को

पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता का विकल्प दिया जाना चाहिए। दोनों राज्य मैत्रीपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा के 3 जिलों पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के कॉलेजों के साथ–साथ पंजाब के मोहाली और रोपड़ जिले के कॉलेजों को भी पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से संबद्धता दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कैंपस हरियाणा में बना रहे हैं। इसके अलावा, आईआईटी, दिल्ली का कैंपस भी हरियाणा में बन रहा है। शिक्षा का विस्तार करने से बच्चों को कई अवसर मिलेंगे। कॉलेज के एफिलिएशन से हरियाणा के छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान हरियाणा के युवाओं और शिक्षा के प्रसार के खिलाफ अड़े रहे।

उन्होंने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता के विषय पर पंजाब असमर्थ है। बैठक में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

में बजट से संबंधित जानकारी देते हुए बताया गया कि पंजाब विश्वविद्यालय वर्षों से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। विश्वविद्यालय में 60 प्रतिशत हिस्सा चंडीगढ़ और 40 प्रतिशत हिस्सा पंजाब का है। पिछले 10 सालों में केंद्र की तरफ से विश्वविद्यालय को 200–300 करोड़ रुपये औसतन प्रति वर्ष मिले हैं। जबकि पिछले 10 सालों में पंजाब से केवल 20–21 करोड़ रुपये औसतन प्रति वर्ष मिले हैं। वर्ष 2020–21 में पंजाब की ओर से 39 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। कुल मिलाकर पंजाब के 40 फीसदी हिस्से के मुकाबले में विश्वविद्यालय को 7–14 फीसदी ही बजट मिल पाता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए हरियाणा अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह

(दिनांक 05.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए हरियाणा के होनहार अभ्यर्थियों के लिए आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सिविल सेवा के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को लोक सेवकों की संज्ञा देते हुए कहा कि वे पूर्ण ईमानदारी, संवेदनशीलता, धैर्य, सेवाभाव और अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अभ्यर्थियों को स्मृति चिन्ह एवं श्रीमदभगवद् गीता भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने प्रतिभावान युवाओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थी हरियाणा उदय व आत्मनिर्भर भारत में अच्छा योगदान देंगें।

अब पूरा देश ही उनके लिए परिवार है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

वसुधैव कुटुम्बकम के भाव के साथ आगे बढना है और समाज को सुखी बनाने के लिए बेहतर कार्य करना है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा के बच्चे प्रतिभावान हैं। इसको लेकर पिछले 8 वर्षो में सरकार ने नया वातावरण तैयार किया गया है। आज उसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश के 6.50 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है।

उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे क्षेत्रों की भी बात करें तो हरियाणा अनेक मामलों में अन्य प्रदेशों से अग्रणीय है। हरियाणा की कुल आबादी 2 प्रतिशत है जबकि रक्षा क्षेत्र में 10 प्रतिशत, खेलों में 35 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र में 15 प्रतिशत हरियाणा का योगदान है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस योगदान को और आगे कैसे बढ़ाया जाए।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2022 की सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में प्रदेश के 63 अभ्यर्थियों और टॉप 100 में 19 अभ्यर्थियों का चयन होना हरियाणा के लिए गर्व का विषय है। इस परीक्षा में 32 लड़के व 31 लड़कियों का चयन होना बेटी बचाओ बेटी पढाओ मुहिम का भी सार्थक परिणाम है। उन्होंने कहा कि पहले जय जवान, जय किसान का नारा था, जिसे आगे बढाते हुए जय विज्ञान, जय अनुसंधान कहा गया। इसमें बाद में जय पहलवान जोड़ा गया और आज इस अवसर पर युवा आगे बढाते हुए जय इम्तिहान का नारा चरितार्थ कर रहे है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक

(दिनांक 06.06.2023)

प्रभाव : प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों में विद्यार्थियों को आने–जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, इसके लिए छोटे वाहनों के माध्यम से छात्रों को आवागमन की सुबविधा प्रदान की जाए। इस कार्य की समुचित मॉनिटरिंग के लिए स्कूल के एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो छात्रों को किराया दिया जाने के संबंध में भी एक प्लान तैयार किया जाए। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करना

साप्ताहिक सूचना पत्र

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार ने एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया है। उन्होंने टीकाकरण प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेवारी भी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है। विभाग आंगनवाड़ी वर्कर्स और एएनएम के साथ मिलकर बच्चों के टीकारकण के लक्ष्य को पूरा करे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग की जिम्मेवारी दी गई है। विभाग की ओर से प्रत्येक बच्चे की ट्रैकिंग की जा रही है और ऐसे बच्चे जो न सरकारी व निजी स्कूलों, न गुरुकुल या मदरसे कहीं भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को ट्रैक कर उन्हें स्कूलों में लाया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति, जिसके पास मकान नहीं है, उसके सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अर्बन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन योजनाओं के अलावा, राज्य सरकार के स्तर पर अलग से भी योजना बनानी पड़े तो बनाएं, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना घर के न रहे।

इसके लिए बैंकों के साथ लिंक करके या राज्य सरकार द्वारा कुछ हिस्सा देकर घर मुहैया करवाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी थी, उनकी दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है।

सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने हेतू विशेष जागरूकता अभियान चलाए और किसानों को

साप्ताहिक सूचना पत्र

अवगत करवाएं कि सॉयल हेल्थ कार्ड के क्या फायदे हैं और फसल पैदावार में यह किस प्रकार सहायक हैं, ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड का धरातल पर पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।परंपरागत कृषि विकास योजना की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसलिए किसान परंपरागत खेती से हटकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक करने के साथ–साथ उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपायुक्तों को जिला स्तरीय दिशा समितियों की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिये ताकि इन बैठकों में उठाये गये सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य स्तरीय दिशा समिति में रखा जा सके। जिससे जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल विचार–विमर्श कर समाधान निकाला जा सके।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जन संवाद पोर्टल के संबंध में प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक

(दिनांक 07.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं व मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। जन संवाद पोर्टल, नगर दर्शन, ग्राम दर्शन पोर्टल और सीएम विंडो शुरू करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे नागरिकों की आवाज सरकार तक सीधे पहुंचे। इसलिए अधिकारी समयबद्ध तरीके से लोगों की शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी प्रतिदिन जन संवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वर्तमान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पिछली सरकारों के बिल्कुल विपरीत है। हम जन सेवा के उद्देश्य से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के

साप्ताहिक सूचना पत्र

उत्थान के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र किसी भी पारदर्शी और प्रभावी सरकार का बेंचमार्क है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर दर्ज प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करते समय शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करना प्रशासनिक सचिवों का मुख्य फोकस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन संवाद पोर्टल नागरिकों के लिए उनकी शिकायतों का आसान समाधान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसलिए सभी प्रशासनिक सचिव और जिला स्तरीय अधिकारी इन समस्याओं व मांगों को गंभीरता से लेकर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में लोगों ने यह बताया है कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन की कई–कई कॉपी भिन्न भिन्न जन प्रतिनिधियों को देते थे, लेकिन कभी उनके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनके कागज व दस्तावेज गुम हो जाते थे। इसी परेशानी को समझते हुए सरकार ने जन संवाद पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर लोगों के लिखित प्रतिवेदन की जानकारी दर्ज की जाती है और संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

खरीफ सीजन 2023–24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी

(दिनांक 07.06.2023)

प्रभाव : माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विपणन सीजन 2023–24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने के निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है।

यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की वचनबद्धता की दिशा में एक और कदम है।

इस बारे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,040 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जबकि ए–ग्रेड धान का एमएसपी 2,060 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मूंग दाल के मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, इसका एमएसपी 7,755 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8,558 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

बाजरा का एमएसपी 2,350 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, रागी का एमएसपी 3578 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3846 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का का एमएसपी 1962 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,090 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर का एमएसपी 6600 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का 6600 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6950 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

इसी प्रकार, मूंगफली का एमएसपी 5850 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6377 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी का एमएसपी 6400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6760 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन का एमएसपी 4300 रुपये

प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4600 रुपये प्रति क्विंटल, कॉटन (मिडियम स्टेपल) का एमएसपी 6080 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6620 रुपये प्रति क्विंटल, कॉटन (लॉन्ग स्टेपल) का एमएसपी 6380 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7020 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से रबी व खरीफ की दोनों फसलों का बुआई सीज़न आरंभ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। सरकार के इस कदम से किसानों के पास यह विकल्प होता है कि उन्हें किस फसल की बुआई करने से अधिक मुनाफा हो सकता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद

(दिनांक 08.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य आदमी की समस्याओं को जानने के लिए सरकार जनता के बीच एक नई कवायद शुरू की है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री तक शिकायतें व सुझाव पहुंचाने के लिए ग्राम दर्शन, नगर दर्शन, सीएम विंडो व जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत की है जिसमें वे स्वयं जनता से फीडबैक लेकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। स्थानीय सांसदों, विधायकों व क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों के साथ आईएएस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में सीधा संवाद भी करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस नई शुरुआत के प्रति लोगों में उत्सुकता बढ़ी है और खुलकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी

बातें रख रहे हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री स्वयं शिकायतकर्ता से सीधे फ़ोन पर बात कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हैं।

इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चार से पांच घंटे सरकार जनता के बीच है और अधिकारियों को वे अपनी समस्याएं खुलकर बता सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों के जीवन को सुगम बनाना है, अधिकारी भी प्रबुद्ध लोगों द्वारा दी गई शिकायतों और सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और हमें सिस्टम को आगे बढ़ाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं आपूर्ति, सिंचाई व जल संसाधन, लोक निर्माण, बिजली, विकास एवं पंचायत, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जैसे प्रमुख विभागों से लोगों की समस्याएं जुड़ी होती हैं और इन्हीं विभागों के अधिकारियों को विशेष रूप से जन संवाद कार्यक्रम में बुलाया गया है ताकि वे भी जनता से सीधा फीडबैक ले सकें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार हर 20 किलोमीटर की परिधि में एक महाविद्यालय खोलने के लिए मैपिंग की गई थी उसी तर्ज पर स्कूल व खेल स्टेडियम की मैपिंग की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व खेल युवाओं के लिए जरूरी हैं। सरकार का लक्ष्य हर एक किलोमीटर के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल, तीन किलोमीटर के क्षेत्र में मिडिल स्कूल व पांच किलोमीटर की दूरी में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और हर क्लस्टर पर स्कूलों में विज्ञान स्ट्रीम हो। उन्होंने कहा कि 5 हजार की आबादी वाले गांवों में पुस्तकालय खोलने की शुरुआत की गई है, इस ओर भी गंभीरता से कार्य करना होगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना (2023–25) का शुभारंभ

(दिनांक 09.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य की द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना (2023–25) का शुभारंभ करते हुए कहा कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति का अग्रदूत रहा हरियाणा अब जल संकट से निपटने और भावी पीढ़ियों को विरासत में जल प्रदान करने के लिए जल क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब इतने बड़े स्तर पर जल संसाधन के लिए कार्य योजना का अनावरण किया गया है। इस कार्य योजना में पानी की कमी और जलभराव की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा बनाई गई ब्लॉक स्तरीय कार्य योजनाएं शामिल हैं। एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना

साप्ताहिक सूचना पत्र

का लक्ष्य पानी की बचत करके दो वर्षों की अवधि में पानी की मांग और आपूर्ति के अंतर को 49.7 प्रतिशत तक पूरा करना है। पहले वर्ष में कुल 22 प्रतिशत पानी और दूसरे वर्ष में 27.7 प्रतिशत पानी बचाना है। यह कदम पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कुल पानी की उपलब्धता 20,93,598 करोड़ लीटर है, जबकि पानी की कुल मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है, जिससे पानी का अंतर 14 लाख करोड़ लीटर है। इस कार्य योजना से अगले दो वर्षों में पानी की बचत करने का लक्ष्य रखा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पानी की अधिकतम मात्रा का उपयोग कृषि और बागवानी क्षेत्र में किया जाता है, जो क्रमशः 86 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है। जल संरक्षण तरीकों को अपनाकर पानी की खपत को कम करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार गिरते भूजल के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाकर लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी।

प्राकृतिक संसाधनों के उपयुक्त उपयोग

के महत्व पर प्रकाश डालते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बेटियों ने हमें आवाज़ दी कि हमें गर्भ में मत मारो तो हमने बेटी बचाओ– बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया और समाज के सहयोग से इसे सफल बनाया।

आज धरती माँ हमें पुकार रही है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें, लेकिन किसी भी कीमत पर उनका शोषण न करें। उन्होंने कहा कि पंचतत्वों को यदि हम देखें तो उसका मतलब भगवान बनता है। भू यानी भूमि (पृथ्वी), ग यानी गगन, अ यानी अग्नि, वा यानी वायु और न यानी नीर या जल होता है। इसलिए हमें अपने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना तैयार करने में सभी संबंधित विभागों के समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होने कहा कि जब हम जल प्रबंधन और संरक्षण की ओर बढ़ते हैं तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रियूज पर हमें फोकस करना होगा। पानी का पुनरू उपयोग करके फ्रेश वॉटर पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।

पीएम–कुसुम योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद

(दिनांक 10.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम–कुसुम योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि ऑफ ग्रिड सोलर पम्प की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है। वर्ष 2020–21 में 15,000 सोलर पम्प स्थापित कर हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा। अब तक 53 हजार सोलर पम्प स्थापित किए गए हैं। यह संख्या पीएम–कुसुम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 50 हजार ऑफ ग्रिड सोलर पम्प से भी अधिक है। प्रदेश में स्थापित 53 हजार सोलर पम्पस से हर साल 29 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली की बचत हो रही है। इससे प्रदेश को 195 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला तो राज्य में केवल 492 सोलर पंप थे। उसके बाद हमने सोलर पंप लगाने के लिए

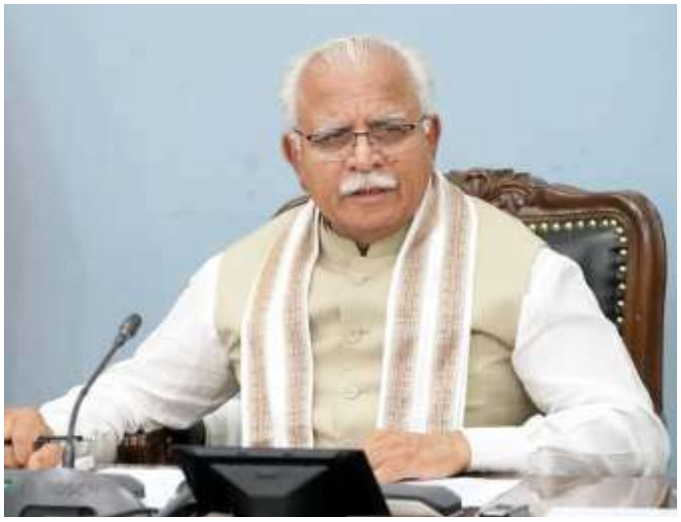

भरसक प्रयास किए। इस वित्त वर्ष के लिए भी 70,000 सौर पंपों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है।

संवाद के दौरान लाभार्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सिंचाई की जरूरतों की पूरा करने के लिए सरकार ने सोलर पंप देकर किसानों को बहुत बड़ा लाभ दिया है। इस योजना में सब्सिडी देकर किसानों को आर्थिक मदद तो मिली ही है, साथ ही कम पानी में अधिक पैदावार मिल रही है। यह बहुत अच्छी योजना

साप्ताहिक सूचना पत्र

है। सोनीपत से जुड़े एक लाभार्थी अमित ने कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बात कर रहे हैं और हमारी समस्याएं सुन रहे हैं। एक अन्य लाभार्थी अशोक कुमार, निवासी झज्जर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। किसानों को इनसे बहुत लाभ हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग किसानों को बहका रहे हैं। एक अन्य लाभार्थी ने कहा कि शुक्रवार से जब से यह संदेश मिला है कि मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, मैं तो कल से ही आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा हूं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाभार्थियों से अनुरोध किया कि वे अन्य किसान भाईयों को भी इस योजना के बारे में बताएं और उन्हें सौर पंप लगवाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

संवाद के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पंप शिफ्ट करने के दौरान गारंटी/वारंटी खत्म हो जाती है, जिससे कठिनाई आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि प्रदेशभर में सोलर पंप की शिफ्टिंग के लिए कंपनी से बातचीत करके एक योजना तैयार की जाएगी, ताकि सोलर पंप सिस्टम की गारंटी/वारंटी कवर जारी रहे। अभी सोलर पंप सिस्टम पर 5 साल की गारंटी मिलती है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में दूसरे चरण का शुभारंभ

(दिनांक 11.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में दूसरे चरण के कार्यों की आधारशिला रखी।। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में 2600 करोड़ रुपये के कार्यों के निर्माण का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह केवल ईंट–सिमेंट का भवन मात्र नहीं अपितु मेरे लिए मेरा एक बड़ा स्वप्न है, जो किसानों की आमदनी को दोगुना करेगा।

हरियाणा के किसानों के साथ फल व सब्जी उत्पादकों, आम लोगों तथा व्यापारियों के लिए खासी लाभकारी सिद्ध होगी। इस मौके पर उन्होंने करीब 55 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इनमें 495 लाख रुपये की लागत से भिवानी में बनाई जाने वाली सब्जी मार्केट, 1204.03 लाख की लागत से भिवानी के सिवानी में नई अनाज मंडी का निर्माण, 894.94 लाख रुपये की लागत से करनाल के असंध में मूनक खरीद केंद्र को सब यार्ड विकसित करने, सिरसा में 2481.38 लाख रुपये की लागत से सब्जी मंडी, अनाज मंडी व लक्कड़ मंडी के विकास के लिए अतिरिक्त मंडी, 192.56 लाख की लागत से कंवरपुरा गांव में खरीद केंद्र का निर्माण तथा 224.47 लाख रुपये की लागत से शेरपुरा गांव में खरीद केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागवानी मंडी के विस्तारीकरण की जानकारी देते हुए कहा कि यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनेगी। इससे उत्तर भारत के राज्यों के क्रेताओं–विक्रेताओं को विशेष लाभ मिलेगा। दिल्ली की आजादपुर मंडी के बेहतरीन विकल्प के रूप में यह मंडी तैयार होगी, जिसमें हर

प्रकार की सुविधाएं मुहैया होंगी। मंडी किसानों की आत्मनिर्भरता के साथ प्रदेश को भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएगी। हरियाणा की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को बढ़ाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी पूर्ति में मंडी की विशेष भूमिका रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से कार्यों को विस्तार दिया जाएगा। जबकि 2600 करोड़ रुपये के टेंडर के कार्यों को दो वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादकों के लिए घोषणा की कि सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को तीन वर्षों के लिए पांच हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों के लिए कुरूक्षेत्र में चार एकड़ भूमि में तेल का कारखाना स्थापित किया जाएगा,

जिसकी क्षमता 20 हजार मिट्रिक टन की होगी।

सुरजमुखी के बीज से तेल व घी का निर्माण किया जाता है। उन्होंने कहा कि करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय आगामी वर्ष शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बागवनी मंडी से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर गन्नौर का रेलवे स्टेशन है, जहां से फल–सब्जियों आदि उत्पादों को लाने–ले जाने की सुविधा रहेगी। यदि आवश्यकता हुई तो मंडी के लिए अलग से भी स्टेशन बनाया जाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जनसम्पर्क कार्यक्रम–करनाल

(दिनांक 11.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल की रामदेव कॉलोनी के वार्ड नंबर–6 में जन संवाद किया। इस जन संवाद के दौरान कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों लोगों ने एक सुर में आवाज उठाई कि वार्ड का 1–1 व्यक्ति मनोहर लाल बनकर जनता के बीच जाएगा और जवाब देगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने न केवल करनाल जिला में बल्कि पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास करवाया है। भविष्य में और भी तेजी से विकास कार्य करवाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसी गांव में तत्काल पाईप लाइन डालने के लिए विभाग को निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश में किसी भी जगह चाहे जो मर्जी विवाद हो लेकिन बिजली और पानी किसी की नहीं रूकेगी।

जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों ने सरकार के विकास कार्यों की जमकर

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार में लोगों को बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां मिली हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वह पूरे प्रदेश में अलग–अलग जगह जन संवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यह सर्वमान्य सत्य है कि हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी हैं। तभी हर कार्यक्रम में आम व्यक्ति सरकार के इस कार्य की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसका असल में हक है, उसे उसका हक मिले, हरियाणा सरकार इस सिद्धांत पर काम कर रही है। इसी के चलते परिवार पहचान पत्र बनाया गया। आज लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते बल्कि घर बैठे बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं। परिवार पहचान पत्र की वजह से ही यह तय हो पाया है कि कौन सरकारी सुविधा का हकदार है और कौन इसका हकदार नहीं है। इससे सैकड़ों लोगों को फायदा मिला है।।

माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सिरसी गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत रखी कि उसके यहां गली में पाईप लाइन न डलने की वजह से पानी नहीं पहुंच रहा। इस पर अधिकारी ने गली के

विषय पर कोर्ट में केस होने का तर्क रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में चाहे जो मर्जी विवाद हो लेकिन किसी के घर में पानी और बिजली नहीं रोकी जाएगी। उन्होंने तत्काल सिरसी की गली में पाईपलाइन बिछाने का निर्देश दिया।

माननीय मुख्यमंत्री जी के जन संवाद कार्यक्रम में आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है, वार्ड नम्बर 7 के लोगों के साथ जन संवाद कार्यक्रम में मौके पर ही पात्र व्यक्तियों की बुढ़ापा पेंशन तथा बीपीएल राशन कार्ड बनवाया गया। अपनी समस्याओं का मौके पर ही समाधान पाकर फरियादी गदगद हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। इतना ही नहीं जब लोगों ने सैक्टर 16 में पानी, सड़क, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज की समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी तो मौके पर ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यक्रारी अभियंता को निर्देश दिए कि इस सैक्टर को नगर निगम को देने के लिए जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करें और अगले 3 महीने के अंदर इसे नगर निगम को सुपुर्द किया जाए ताकि यहां की हर समस्या का समाधान नगर निगम द्वारा करवाया जा सके और लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिल सके।

जन संवाद मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व पार्षद स्व. सुदर्शन कालड़ा को याद किया और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार को 9 साल व राज्य सरकार को साढ़े 8 साल काम करते हो गए हैं। जिससे देश व प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा आज विदेशों में भी हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। कईं ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक बार कईं मंचों पर की है। इतना ही नहीं लाल डोरा मुक्त योजना को पूरे देश में भारत सरकार ने लागू किया है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र योजना की भी

साप्ताहिक सूचना पत्र

भूरी–भूरी प्रशंसा की जा रही है और मुख्यमंत्रियों को इस योजना का अध्ययन करने के लिए कहा गया है, यदि यह योजना अच्छी है तो इसे अपने प्रदेशों में भी लागू करें।

उन्होंने कहा कि यह साल चुनावी मौसम का शुरू हो चुका है और इसमें अब सभी राजनीतिक दलों के लोग बाहर निकलेंगे। अगर हमने अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किया है तो हमें दोबारा मौका दें।

जन संवाद कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि मुख्यमंत्री जी का नाम मनोहर है और इनके काम भी मनोहर हैं, निराले हैं। हमने अपने जीवनकाल में पहले ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं जो पब्लिक के हाथ में माईक देकर उसकी समस्या सुनते हैं और मौके पर ही उसका समाधान कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है।